24 sep 2025:Layout 1 9/24/2025 7:10 AM Page 1

हिन्दी दैनिक

मूलनिवासी नायक

www.mulnivasinayak.com

डाक पंजी.सं. एसएसपी/एलडब्लू./एनपी.–343/2018–20

व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित

वर्ष 14 | अंक 374 | पृष्ठ 2 | बुधवार 24 सितंबर, 2025 | मूल्य 2 + वितरण व ट्रान्सपोर्ट 1 रू. कुल 3 रूपये | RNI NO. UPHIN/ 2011/ 41813

दैनिक
मूलनिवासी नायक
स्थापना दिवस
पर सभी पाठकों को दैनिक मूलनिवासी परिवार की ओर से ढेर सारी
हार्दिक बधाई
nayakmulnivasi@gmail.com
9506833426, 9664642213

कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा आज का भारत

सबसे बड़ी 'कर्जदार' मोदी सरकार

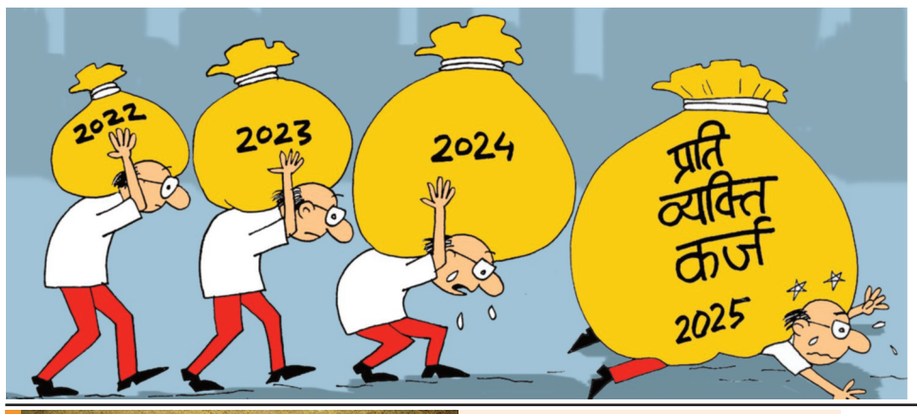

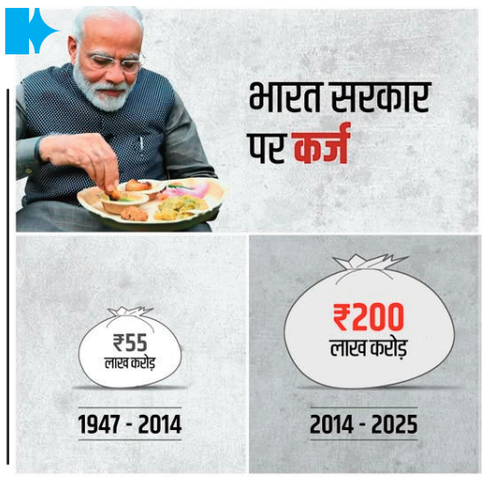

हर भारतीय 4.8 लाख का कर्जदार

हर दिन औसतन 19 लोग कर्ज के बोझ के चलते कर रहे आत्महत्या

देश में हर दिन औसतन 19 लोग कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि करोड़ों आम लोग अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं। करोड़ों मध्य वर्ग के लोग, नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यवसायी और किसान जब घर की ज़रूरत की चीजों को ख़रीदते हैं, तब उस पर भी मोटा जीएसटी देते हैं। मोटरसाइकिल, बच्चों को पढ़ाने, घर में बिटिया की शादी और बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जैसी ज़रूरतों के लिए उन्हें मोटी ईएमआई पर बैंकों या मोटे ब्याज पर निजी साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। आपकी कर्ज की एक किस्त छूट जाए तो फ़ोन पर, दरवाज़े पर वसूली एजेंटनुमा गुंडे भेजे धमकाने चले आते हैं और 2–3 किस्त छूट जाने पर तो घर–ज़मीन–खेत पर नोटिस लग जाती है। लेकिन आपके ही टैक्स के पैसे से बड़े–बड़े पूँजीपतियों का कर्ज माफ होता है और न तो उनके घर कर्ज वसूली के लिए गुंडे जाते हैं, न ही कोई नोटिस।

क्या आपको पता है कि देश के बैंकों ने सिर्फ पिछले पांच साल में 9.90 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाला। इसमें से मात्र 18 प्रतिशत वापस वसूले जा सके। 81 प्रतिशत से ज्यादा की रकम एक तरह से माफ की जा चुकी है। ये कर्जमाफ़ी उन पूँजीपतियों के लिए थी जिनसे सरकार टैक्स भी कम ले रही है, जिन्हें कर्ज न लौटाने पर थाली में सजाकर कर्जमाफी भी दी जा रही है।

भाजपा सरकार की इस अर्थनीति को ज़रा देखिए, जहाँ एक तरफ आम लोग, छोटे व्यापारी और किसान टैक्स, महंगाई और कर्ज का दंश झेलते हुए अपना जीवन खत्म करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के चंद उद्योगपति मित्रों के लिए ऐसी नीति बनाई गई है कि उनका अरबों–खरबों का कर्ज चुटकी बजते ही माफ हो जाता है। न तो कोई वसूली का सिस्टम है, न ही कर्ज लौटाने की ज़िम्मेदारी। इस दोहरी व्यवस्था में वो आम लोग पिस रहे हैं, जो ज़रा सा कर्ज न चुका पाने के चलते अपना जीवन खत्म करने को मजबूर हैं।

नई दिल्ली। ब्यूरो

भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में यह 3.9 लाख रुपए था। बीते दो साल में इसमें 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यानी, हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग पहले से ज्यादा उधार ले रहे हैं। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अन्य रिटेल लोन शामिल हैं। नॉन–हाउसिंग रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये लोन टोटल डोमेस्टिक लोन का 54.9 प्रतिशत हिस्सा है। ये डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने योग्य आय) का 25.7 प्रतिशत है। हाउसिंग लोन का हिस्सा 29 प्रतिशत है और इसमें भी ज्यादातर उनका है जो पहले से लोन लेकर दोबारा से ले रहे हैं।

आरबीआई के मुताबिक, भारत के कुल जीडीपी का 42 प्रतिशत कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कम है, जहां ये 46.6 प्रतिशत है। यानी, भारत में कर्ज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। साथ ही, ज्यादातर बॉरोअर्स अच्छी रेटिंग वाले हैं, यानी इनसे पैसा डूबने का खतरा कम है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस कर्ज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतर रेटिंग वाले हैं। वे कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। साथ ही, कोविड–19 के समय की तुलना में डेलिक्वेंसी रेट यानी कर्ज न चुका पाने की रेट में कमी आई है। हालांकि जिन लोगों की रेटिंग कम है और कर्ज ज्यादा है, उनके लिए थोड़ा जोखिम है। इसके साथ ही माइक्रोफाइनेंस सेक्टर (छोटे लोन ग्रुप) में कर्ज लेने वालों की एवरेज लायबिलिटी 11.7 प्रतिशत तक कम हुई है, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही में स्ट्रेस्ड असेट्स की संख्या बढ़ी है। ट्ठप् ने कहा है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां ज्यादा ब्याज दरें और मार्जिन वसूल रही हैं। जो कर्ज लेने वालों के लिए चुका पाना मुश्किल हो रहा है।

भारत पर बाहरी कर्ज

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों बाहरी कर्ज 736.3 बिलियन डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है। यह जीडीपी का 19.1 प्रतिशत है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन–फाइनेंस कॉर्पोरेशन्स का 35.5 प्रतिशत, डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं का 27.5 प्रतिशत और सरकारों का 22.9 प्रतिशत है। अमेरिकी डॉलर में लिया गया कर्ज टोटल एक्सटर्नल डेट का 54.2 प्रतिशत है।

भुखमरी के कगार पर झारखंड के लाखों परिवार

रायपुर। ब्यूरो

झारखंड में ई–केवाईसी के चक्कर में लाखों राशन कार्डधारक अटक गए हैं। प्रशासनिक खामियों के चलते इन नागरिकों को राशन नहीं मिल रहा है। इस तरह गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे इस राज्य में भूख का खतरा बढ़ सकता है। जन वितरण प्रणाली में ई–केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर) एक आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। यह ई–पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक या 'मेरा ई–केवाईसी' ऐप से चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए की जाती है, ताकि डुप्लीकेट और अयोग्य कार्ड हटाए जा सकें और जरूरतमंद नागरिक शामिल किये जा सकें। केंद्र सरकार ने इसे सभी राशनकार्ड धारकों के लिए अनिवार्य कर 30 जून 2025 तक की समयसीमा तय की थी। समय सीमा के बाद सब्सिडी रोकने का निर्देश भी जारी किया गया था।

5 अगस्त 2025 तक झारखंड में 72.9 लाख राशनकार्ड धारकों के ई–केवाईसी नहीं हुए थे। इनमें 14.6 लाख के आधार नंबर राशनकार्ड से लिंक ही नहीं हैं, जो ई–केवाईसी प्रक्रिया से तुरंत बाहर हो जाते हैं। नवंबर 2024 से जून 2025 तक चली प्रक्रिया में कई अड़चनें रहीं– 2जी मशीनें, नेटवर्क की अनुपलब्धता, ठप सर्वर और धीमा इंटरनेट, बायोमेट्रिक फेल होना, आधार में मोबाइल नंबर न जुड़ना और राशनकार्ड में गलत आधार सीडिंग.

हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने दिसंबर 2024 में पत्र जारी कर माना था कि सर्वर पर लोड बढ़ने से न राशन वितरण हो पा रहा था, न ई–केवाईसी। इन कारणों से कार्डधारकों को अक्सर जन वितरण प्रणाली की दुकान, प्रखंड कार्यालय, आधार केंद्र और प्रज्ञा केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़े। वहीं प्रवासी मज़दूरों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्डधारकों के लिए ई–केवाईसी की प्रक्रिया उनकी पहुंच से बाहर रही। मई 2025 तक मनिका प्रखंड के 1120 आदिम जनजाति कार्डधारियों में से 797 (71 प्रतिशत) का ई–केवाईसी नहीं हो पाया था। कुल आदिम जनजाति कार्डधारकों में से 21 प्रतिशत के आधार नंबर राशनकार्ड से जुड़े ही नहीं थे।

बता दें कि केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक विफलता झेलने वालों को चिह्नित करने, अनुपस्थित लाभार्थियों को ट्रैक करने और ई–केवाईसी नहीं होने के कारण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। झारखंड सरकार ने राशन डीलरों से कारण दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एक समान फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराया गया, कारण अलग–अलग तरीके से लिखे गए और आंकड़ों की डिजिटल प्रविष्टि ही नहीं हुई। अब तक राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ई–केवाईसी न होने पर कार्डधारकों का क्या होगा

यह भी बता दें कि 2016–18 में आधार सीडिंग (अपने बैंक खाते या अन्य पहचान दस्तावेजों को अपने आधार नंबर से जोड़ना) न होने के कारण झारखंड में 11 लाख से अधिक राशनकार्ड रद्द हुए थे, जिसका परिणाम था की 17 लोगों की भूख से मौत हुई थी. यदि इस बार भी ई–केवाईसी के नाम पर योग्य कार्डधारकों के कार्ड रद्द हुए, तो लाखों लोग भूख और कुपोषण की ओर धकेले जा सकते हैं।

छात्रसंघ चुनाव में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने उतारा उम्मीदवार

छात्रों के अधिकार के लिए जान की बाजी लगा देंगे : बृजेश कुमार

उत्तरकाशी। प्रतिनिधि

मंगलवार 23 सितंबर, 2025 को रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में नूतन शैक्षणिक सत्र 2025–26 के छात्रसंघ चुनाव में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा (भाविमो) छात्र संगठन से महासचिव पद हेतु बृजेश कुमार ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन के बाद उत्तरकाशी शहर में एक भव्य नामांकन रैली का आयोजन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन हुआ। महासचिव प्रत्याशी बृजेश कुमार ने नामांकन रैली में सम्मलित समस्त शुभचिंतकों का आभार जताया।

रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

- महासचवि पद लिए भरा नामांकन पत्र
- उत्तरकाशी शहर में नामांकन के बाद भव्य रैली

24 sep 2025:Layout 1 9/24/2025 7:11 AM Page 2

संपादकीय — मूलनिवासी संदेश

कर्ज का दलदल

भारत के लगभग सभी राज्य कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं. विकास कार्यों से लेकर अपनी जरूरतों के अनुसार राज्यों द्वारा समय–समय पर केंद्र सरकार, ट्ठप् या अन्य वित्तीय एजेंसियों से कर्ज लिया जाता है. राज्यों की ओर से लिए गए कर्ज का पहाड़ साल दल साल ऊंचा होता जा रहा है. जिसकी अदायगी के लिए राज्यों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों और केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है जो वित्त वर्ष 2024–25 की समाप्ति तक 8 लाख 34 हजार 543 करोड़ के पार पहुंच जाएगा. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (7,69,245.3 करोड़), तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (7,22,887.3 करोड़), चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल (6,58,426.2 करोड़), पांचवें नंबर पर कर्नाटक (5,97,618.4 करोड़), छठे नंबर पर राजस्थान (5,62,494. 9 करोड़), सातवें नबंर पर आंध्र प्रदेश (4,85,490.8 करोड़), आठवें नबंर पर गुजरात (4,67,464.4 करोड़), नौवें नंबर पर केरल (4,29,270.6 करोड़), दसवें नंबर पर (मध्य प्रदेश 4,18,056 करोड़), ग्यारहवें नंबर पर तेलंगाना (3,89,672.5 करोड़) और 12वें नंबर पर बिहार (3,19,618.3 करोड़) शामिल है.

कर्ज लेने के मामले में छोटे राज्य भी पीछे नहीं हैं. कर्ज के दलदल में फंसे कुछ छोटे राज्यों ने तो कुछ बड़े राज्यों से भी अधिक कर्ज लिया है. छोटे राज्यों में कर्ज लेने के मामले में पंजाब टॉप पर है. पंजाब पर वित्त वर्ष 2024–25 तक की समाप्ति पर 3,51,130.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा. इसी तरह दूसरे नंबर पर मौजूद हरियाणा पर भी 3,36,253 करोड़ का कर्ज हो जाएगा. खास बात ये है कि पंजाब और हरियाणा का कर्ज बड़े राज्यों की सूची में शुमार बिहार से अधिक है. छोटे राज्यों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर असम (1,50,900.4 करोड़), चौथे नंबर पर झारखंड (1,31,455. 6 करोड़), पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ (1,22,164.1 करोड़), छठे नंबर पर ओडिशा (1,20,986.9 करोड़) और सातवें नंबर पर गोवा (34758.4 करोड़) है.

देश के छोटे–छोटे पहाड़ी राज्य भी कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं. इनमें से सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा. कर्ज के बोझ तले दबते हिमाचल में आलम ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह चुके हैं कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. ये हाल उस प्रदेश का है जहां कि आबादी महज 70 लाख के करीब है. जो इस सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद उत्तराखंड से भी कम है. उत्तराखंड पर वित्त वर्ष 2024–25 की समाप्ति पर कर्जका बोझ 89466 करोड़ हो जाएगा. कर्जदार पहाड़ी राज्यों की सूची में तीसरे नंबर पर त्रिपुरा (26505.8 करोड़), चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश (21654.2 करोड़), पांचवें नंबर पर मेघालय (20029.9 करोड़), छठे नंबर पर मणिपुर (19245.8 करोड़), सातवें नंबर पर नागालैंड (18165.8 करोड़), आठवें नंबर पर सिक्किम (15529.5 करोड़) और नौवें नंबर पर मिजोरम (14039.3 करोड़) शामिल है.

वैसे तो कर्ज का प्रावधान विकास कार्यों के लिए होता है लेकिन राज्यों में सब्सिडी और धुआंधार बंटती मुफ्त की रेवड़ियों ने आज लगभग हर राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर ब।ळ की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है. कई जगह सब्सिडी की जगह मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है. सरकारें पैसा ऐसी जगह खर्च रही हैं जहां से कमाई जीरो होगी. मुफ्त बिजली–पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं. जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता पाना होता है. ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंस रहे हैं. इस अलावा राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जा रहा है. फिर चाहे पंजाब हो या हिमाचल या फिर तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश. उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य का यही हाल है.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का मानना है कि खर्च ज्यादा और आय कम तो इसी पर विचार करने की जरूरत है. नेताओं का जोर सत्ता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर है. जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है और जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है. केआर भारती कहते हैं कि राज्यों को सब्सिडी और मुफ्त बिजली, पानी बांटने की बजाय आर्थिक संसाधन जुटाने की ओर गंभीरता से सोचना चाहिए. वो हिमाचल के संदर्भ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बागवनी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हैं. इसी तरह अन्य राज्यों को भी अपनी क्षमताओं के देखते हुए संसाधन जुटाने की नसीहत देते हैं. केआर भारती के मुताबिक राज्यों को बेवजह के खर्चों के साथ–साथ लोकलुभावन घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी. इसपर हर सियासी दल को एक मंच पर आना होगा क्योंकि ये राज्य के भविष्य का सवाल है. केआर भारती कहते हैं कि राज्यों में एक मंत्री के पास कई विभाग होते हैं लेकिन उसके काफिले में हर विभाग की गाड़ियां अटैच होती हैं, जिन्हें कम किया जा सकता है.

बिहार में आम जनता का हाल बेहाल

बिना पुल के कैसे पार होगा विजय रथ

पटना। ब्यूरो

अलौली विधानसभा (सुरक्षित) क्षेत्र राजनीतिक दिग्गजों की धरती है। इस विधानसभा क्षेत्र का प्रति. निधित्व दिग्गज कांग्रेस नेता मिश्री सदा और प्रसिद्ध एससी से नेता रामविलास पासवान ने भी किया है। अभी भी दो बड़े राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा जुड़ाव अलौली विधानसभा क्षेत्र से है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का जन्मस्थान अलौली विधानसभा क्षेत्र का शहरबन्नी गांव है। वे अलौली विधानसभा क्षेत्र का सात दफा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि लोजपा (राम. विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पैतृक गांव शहरबन्नी है। वर्तमान में यहां से राजद के फायर ब्रांड नेता रामवृक्ष सदा विधायक हैं, परंतु आज भी अलौली विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। एक बड़ी आबादी आज भी समुचित आवागमन की सुविधा से वंचित है। जिन्हें प्रखंड मुख्यालय अलौली पहुंचने के लिए नाव से नदी पार करना पड़ता है। बागमती नदी का गढ़ घाट फरकिया के प्रमुख घाटों में से एक है। अलौली प्रखंड मुख्यालय से गढ़ घाट की दूरी लगभग तीन किलोमीटर है। वहीं अलौली रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग पांच सौ मीटर है। आनंदपुर मारण पंचायत, चेराखेरा पंचायत, रामपुर अलौली पंचायत की एक हिस्सा, सोनमनकी मुसहरी, परास–वार्ड नंबर आठ और हथवन पंचायत की सिसवा–बिंद टोली बागमती नदी के पार है। यहां के लोग विभिन्न जगहों से नाव पकड़कर अलौली गढ़ घाट पहुंचते हैं। फिर वहां से आटो–टोटो पकड़कर प्रखंड मुख्यालय अलौली आते हैं। उन्होंने बीमार पड़ने पर अलौली सीएचसी भी नदी पार कर ही आना पड़ता है।

रामपुर अलौली पंचायत, नगर पंचायत अलौली और अंबा इचरुआ पंचायत के अधिकांश किसानों की खेती, पशुपालन नदी पार ही है। उन्हें भी नाव से बागमती पार आना–जाना पड़ता है। श्याम घरारी के समीप कोसी नदी के कित्ता घाट पर कई वर्षों से पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जो अधूरा है।

बीते 20 जुलाई 2025 को इस घाट को नाव से पार करने के दौरान हन्ना, वार्ड नंबर–पांच के नंदू चौधरी नदी में गिर पड़े और डूबने से उनकी मौत हो गई। अलौली गढ़ घाट पर लंबे आंदोलन के बाद पुल निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू हुआ है। इस पुल निर्माण का लक्ष्य 27 मई 2027 है। अब देखना है कि ससमय पुल का निर्माण हो पाता है या नहीं। फिलहाल नाव से ही स्थानीय लोग गढ़ घाट को पार करते हैं। ग्राम पंचायत राज आनंदपुर मारण की पंचायत समिति सदस्य सुनैना देवी कहती हैं– अभी आश्विन माह में बागमती उफान पर है। नाव से बागमती पार कर गढ़ घाट पहुंचते हैं, फिर वहां से तीन किलोमीटर की दूरी तय कर अलौली प्रखंड मुख्यालय जाते हैं। प्रतिदिन पंचायत के दर्जनों लोगों को किसी न किसी काम से अलौली जाना पड़ता है। वर्षा होने और तेज हवा चलने पर नाव परिचालन बंद हो जाता है।

बुलडोजर कार्रवाई पर दिए फैसले से बड़ी संतुष्टि मिली : सीजेआई

नई दिल्ली। ब्यूरो

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई पर दिए फैसले से उन्हें बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि यह मानवीय समस्याओं से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर न्याय की तुलना एक अराजक स्थिति से की थी और देशभर के लिए दिशा–निर्देश तय किए थे।

एक कार्यक्रम में सीजेआइ गवई ने कहा कि उन्हें जस्टिस विश्वनाथन के साथ करीब छह माह तक पीठ साझा करने का अवसर मिला। इस दौरान पीठ ने अभियुक्तों या दोषियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के खिलाफ कई निर्देश पारित

किए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बुलडोजर से जुड़ा निर्णय उन फैसलों में से एक है जिसने हम दोनों को अत्यधिक संतुष्टि दी। इसके मूल में मानवीय समस्याएं थीं। परिवारों को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा था कि उनके सदस्य अपराधी या आरोपित हैं।'

सीजेआइ ने यह भी कहा कि इस फैसले का श्रेय उन्हें ही नहीं, बल्कि जस्टिस विश्वनाथन को भी जाता है। उन्होंने कहा कि सीजेआइ के कार्यकाल का न्याय प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता। सीजेआई ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रधान न्यायाधीश के कार्यकाल का न्याय प्रशासन की दक्षता से कोई सीधा सं. बंध है। हमारे पास ढाई महीने तक जस्टिस ललित और जस्टिस संजीव खन्ना जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है तथा वे न्याय प्रदान करने और न्याय प्रशासन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।

सीजेआइ ने कहा, मैंने न्याय प्रशासन की बेहतरी और देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने हर पल प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे युवा वकीलों को अच्छा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।

मानवता की धरोहर

बुद्ध का मार्ग केवल धम्म का मार्ग नहीं, बल्कि मानवता का मार्ग है।

राजा चौरे
संपादक, एमएन टीवी

छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले में महानदी के किनारे बसा छोटा–सा कस्बा सिरपुर आज भले ही एक शांत गाँव की तरह दिखाई देता हो, लेकिन इसकी धरती पर चलते ही लगता है जैसे इतिहास की परतें खुल रही हों। यहाँ के हर खंडहर, हर स्तूप और हर विहार की दीवारें उस स्वर्णिम युग की गवाही देती हैं, जब सिरपुर बौद्ध धम्म का एक प्रमुख केंद्र था। छठी से दसवीं शताब्दी के बीच सिरपुर दक्षिण कोसल की राजधानी रहा। यह वही समय था जब बौद्ध धम्म अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के चरम पर था। इस क्षेत्र के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बौद्ध धम्म को संरक्षण दिया। उन्होंने भिक्खुओं को भूमि और अनुदान दिए, विहारों का निर्माण कराया और साधना व शिक्षा को बढ़ावा दिया।

इतिहास की एक और अहम गवाही चीन के यात्री ह्वेनसांग के लेखों में मिलती है। सातवीं शताब्दी में जब उन्होंने भारत की यात्रा की, तो सिरपुर का विस्तार और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखकर वे अभिभूत हो गए। उन्होंने लिखा कि इस नगर में सौ से अधिक बौद्ध विहार और हज़ारों भिक्खु मौजूद थे जो दिन–रात साधना और अध्ययन में लीन रहते थे। ह्वेनसांग का यह विवरण हमें यह समझाता है कि सिरपुर नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की श्रेणी में आता था। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ से बौद्ध दर्शन और करुणा का संदेश पूरी दुनिया तक फैलाया जाता था।

सिरपुर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ मिले बौद्ध विहार और स्तूप हैं। आनंदप्रभु कुटी विहार, स्वस्तिक विहार और कई छोटे–बड़े मठ यहाँ की खुदाई से सामने आए हैं। आनंदप्रभु कुटी विहार की संरचना और प्रांगण बताते हैं कि यह स्थान केवल पूजा–अर्चना के लिए नहीं, बल्कि अध्ययन और साधना के लिए भी इस्तेमाल होता था। यहाँ भिक्खु रहते थे, वे बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करते और अनुशासन के साथ जीवन जीते। स्वस्तिक विहार का नाम इसकी संरचना से पड़ा है। यह विहार अपने स्थापत्य की वजह से अनोखा है। यहाँ की दीवारों पर बनी नक्काशियाँ बौद्ध प्रतीकों–धर्मचक्र, कमल और बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती हैं। इन विहारों के अलावा यहाँ अनेक स्तूप भी मिले हैं। स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल बुद्ध के अवशेषों को संजोए रखने का स्थान होता था, बल्कि यह श्रद्धा और साधना का भी केंद्र था।

बुद्ध का दर्शन सरल था–मध्यम मार्ग अपनाओ, करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बनाओ। सिरपुर के भिक्खु इस संदेश को जीते थे और समाज तक पहुँचाते थे। यहाँ भिक्खु ध्यान साधना करते, बौद्ध सूत्रों का अध्ययन करते और एक–दूसरे के साथ ज्ञान साझा करते। यहाँ से अनेक भिक्खु दक्षिण–पूर्व एशिया तक गए और बुद्ध का संदेश दूर–दूर तक फैलाया। सिरपुर इस दृष्टि से केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक वैश्विक केंद्र था जिसने बौद्ध धम्म के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को मजबूत किया। सिरपुर केवल छत्तीसगढ़ की धरोहर नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की धरोहर है। यहाँ की ईंटें और खंडहर हमें अतीत की उस आवाज़ को सुनाते हैं, जिसमें बुद्ध की करुणा और साधना की गूंज अब भी मौजूद है। आज समय की मांग है कि हम सिरपुर जैसे स्थलों को न केवल संरक्षित करें, बल्कि उनसे सीख भी लें। क्योंकि बुद्ध का मार्ग केवल धम्म का मार्ग नहीं, बल्कि मानवता का मार्ग है।

शिक्षित करो संगठित करो संघर्ष करो
समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए

बामसेफ एवं ऑफसूट संगठन

केन्द्रीय कार्यालय : म.न. 11263 / 14 (ग्राउण्ड फ्लोर) केलाकोठी, डोरीबालान करोलबागरू नई दिल्ली–110005, दूरभाष 011–647035902
प्रान्तीय कार्यालय : जी–14 यूपीएसआईडीसी, सरोजनीनगर, कानपुर रोड लखनऊ सम्पर्क सूत्र – 8423606443, 8218619431

बांदा मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

स्थान : राजमहल पैलेस (श्याम पैलेस के सामने) छतरपुर रोड, महोबा
उद्घाटक : मा0 जफरउल्ला खां उर्फ छक्कन हाजी जी (मुस्लिम स्कॉलर)महोबा
प्रशिक्षक : मा॰ प्रो. डॉ. मायाशंकर कौशल जी (सीईसी मेम्बर एवं केन्द्रीय पर्यवेक्षक बामसेफ नई दिल्ली)
दिनांक : 28 अक्टूबर 2025 दिन रविवार समय : सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक

1. विशिष्ट अतिथि – मा0 सीमा कुशवाहा जी (ब्लॉक प्रमुख चरखारी ब्लॉक)महोबा
2. विशिष्ट अतिथि – मा0 वी.पी. निर्मल जी (से.नि.प्रवक्ता चित्रकूट इण्टर कालेज) कर्वी
3. विशिष्ट अतिथि – मा0 मीरा भारती जी (जिला पंचायत सदस्य वार्ड नम्बर 16 सरईयॉ) चित्रकूट
4. विशिष्ट अतिथि – मा0 राजेन्द्र सिंह कुशवाहा जी (प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा उ0प्र0) बांदा
5. विशिष्ट अतिथि – मा0 रमेशचन्द्र कुशवाहा जी (से.नि.कृषि रक्षा अधिकारी चित्रकूट)कर्वी
6. मुख्य अतिथि - मा॰ सी.एल. साहू जी (से.नि. जिला बवत अधिकारी महोबा हमीरपुर) महोबा
7. प्रमुख उपस्थिति - डॉ. सबीहा रहमानी जी (प्राचार्य राजकीय महिला डिग्री कॉलेज) बांदा

रजिस्ट्रेशन शुल्क – विद्यार्थी,युवा,बेरोजगार – 50/ रुपये
भारत मुक्ति मोर्चा (मजदूर,किसान,छोटे व्यवसायी आदि एवं संविदा कर्मचारी) 100/ रुपये
सरकारी कर्मचारी – 300/ रुपये, अधिकारी 500/ रुपये
,वकील,डाक्टर,इंजीनियर्स एवं जनप्रतिनिधि – 500/ रुपये

जय मूलनिवासी

निवेदक – बामसेफ एवं ऑफसूट संगठन, मंडल इकाई बांदा मंडल
मो0 : 9368982616, 9506121736

'मूलनिवासी नायक' यह दैनिक पेपर, मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक शांताराम हरी रणशृंगारे इन्होंने छत्रपति प्रिंटर्स, 570/28 ए. वी.आई.पी. रोड, विराट नगर, आलमबाग, लखनऊ यहाँ से मुद्रित करके, मकान नं. ए–1461, सेक्टर आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. से प्रकाशित किया. संपादक – इं.आर.के.राम, संस्थापक संपादक – शांताराम हरी रणशृंगारे, प्रधान संपादक– राज कुमार, मुख्य संपादक– राज कुमार RNI NO. UPHIN/2011/41813 सम्पर्क : . Whatsapp : 9506833426, Office: 9506833426
Website : www.mulnivasinayak.com - Email : - nayakmulnivasi@gmail.com